

the scarcity areas of Rajasthan as a famine relief measure on a priority basis. Most of its rigs have been withdrawn from the exploration work and diverted to Rajasthan. The number

of tubewells, including those in Rajasthan, drilled by the Exploratory Tubewell Organisation during 1964-65 is given below:—

Name of State	Total bores drilled	Successful drilled
<i>Work on behalf of State Governments etc.</i>		
1. Rajasthan	85	53
2. Bihar	63	62
3. Maharashtra	3	2
4. Kutch (Gujarat)	47	39
5. U. P.	12	12
6. Delhi	1	1
7. Mirdhya Pradesh	1	1
TOTAL	212	175

(c) The programme of work for 1965-66 is as follows:—

I. Programme of drilling exploratory bores :

State	No. of exploratory bores to be drilled.
Himachal Pradesh.	1
Uttar Pradesh.	4
TOTAL	5

II. Programme of drilling tubewells on behalf of State Governments.

State	Total No. of bores
Bihar	61
Kutch (Gujarat)	44
Rajasthan	127
Uttar Pradesh	8
Delhi	12
TOTAL	252

पंजाब की अनुसूचित आदिम जातियों की सूची

1601. श्री हेम राज : क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने अनुसूचित आदिम जातियों की सूची केंद्रीय सरकार को भेज दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उन आदिम जातियों के नाम क्या हैं तथा वे किस-किस जिले में रहती हैं ।

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उप-मंत्री (बीमती चन्द्र शेखर) : (क) प्रौर (ख) राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 342 (1) के अधीन पंजाब में अनुसूचित आदिम जातियों की सूची उल्लिखित कर दी है प्रौर यह निम्न-लिखित है :—

कांगड़ा जिले में म्पीती प्रौर लाहोल में :—

1. गड्डी ।
2. सबगला ।
3. प्रीत या बौघ

पंजाब सरकार द्वारा आदिम जातियों की सूची केन्द्रीय सरकार को भेजने का प्रश्न नहीं उठता ।

Central Road Fund

1602. Shri Karni Singhji: Will the Minister of Transport be pleased to state:

(a) the amount of the grant given to the Rajasthan Government for the Central Road Fund for road development schemes in the State during 1964-65; and

(b) the amount proposed to be allotted for the year 1965-66?

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur): (a) Rs. 27.12 lakhs.

(b) Rs. 27.73 lakhs.

दिल्ली के इंद-गिंद कृषि योग्य भूमि

1603. श्रीरामानन्द शास्त्री : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली के इंद-गिंद कितनी कृषि योग्य भूमि बेकार पड़ी है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस भूमि का खेती अथवा सब्जिया पैदा करने के लिए उपयोग करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) (1) दिल्ली के प्रायोजित विकास हेतु दिल्ली प्रशासन द्वारा अधिग्रहण किया जाने वाला घोषित भूमि क्षेत्र 50,000 एकड़ है ।

(2) अधिग्रहण किया हुआ क्षेत्र और जिसको अधिकार में लिया जाना है वह 20,000 एकड़ है ।

(3) दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली

नगर निगम, सरकारी विभाग, सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्था, औद्योगिक संपदा, को-ऑपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसायटी आदि को विकास के कार्यों के लिए पहले ही जो क्षेत्र सुपुर्द किया हुआ है वह 11,500 एकड़ है । शेष भूमि का वितरण भी किया जा रहा है ।

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा एक प्रस्ताव पर विचार हो रहा है जिसके अनुसार अधि-ग्रहण की हुई कृषि भूमि विभागीय रूप से तब तक जोती जाएगी जब तक यह भूमि मास्टर प्लान के अन्तर्गत विभिन्न कार्य के लिए नहीं ली जाती ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

Wheat from Canada

1994. { Shri Ram Harkh Yadav:
Shri Murli Manohar:
Shri E. S. Pandey:
Shri E. Barua:

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have entered into a contract recently with Canada for the supply of a large quantity of Canadian wheat;

(b) if so, the details thereof;

(c) the quantity of wheat tonnage involved; and

(d) when the shipment of wheat is likely to arrive in India?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D. R. Chavan): (a) to (d). The Government of Canada have recently made an allocation of \$10 million as an aid for the purchase of Canadian wheat under their International Food Aid Programme for 1965-66. This amount would realise about 1.36 lakh tonnes of wheat which is likely to arrive in India during the period September to November, 1965.